

रिपोर्टः भारत में लगभग 20% एमएसएमई का स्वामित्व महिलाओं के हाथों में है महिला उद्यमिता की भागीदारी बढ़ी, 1.57 करोड़ महिलाएं दे रहीं योगदान

वर्तमान में महिलाएं उद्यमिता (एंटरप्रेन्योरशिप) के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंटरप्रेन्योरियल स्प्रिट स्टूडेंट्स सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल उद्यम गतिविधियों में महिला उद्यमियों की भागीदारी अब पुरुषों के लगभग बराबर है। महिला उद्यमिता की दर 11.4% है, जबकि पुरुषों में यह दर 11.6% है। आकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 20% सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यवसाय महिलाओं के स्वामित्व में हैं। लगभग 1.57 करोड़ महिलाओं द्वारा संचालित उद्यम अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भारत में महिला उद्यमियों द्वारा लगभग 2.2 से 2.7 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जा रहा है।

महिला उद्यमियों के योगदान को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, महिला ई-हाट और अन्य योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं को 10 लाख से 1 करोड़ तक के क्रेडिट मिलने का प्रावधान है। नीति आयोग की वीमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म महिलाओं को उनके व्यवसायों को विकसित करने के लिए डिजिटल और नेटवर्किंग अवसर प्रदान करती है। हालांकि नीतिगत समर्थन के सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं, लेकिन महिला उद्यमियों के सामने चुनौतियां अभी भी कम नहीं हुई हैं। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के व्यवसायों की संख्या अधिक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच की कमी के कारण यह संख्या सीमित है। कुछ राज्य इन असमानताओं को कम करने के लिए प्रयासरत



डॉ. सुनील शुक्ल
महानिदेशक, भारतीय
उद्यमिता विकास
संस्थान
(ईआईआइआइ),
अहमदाबाद
[@patrika.com](http://patrika.com)

हुई, जिसने भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत बनाया। डीपीआईआईटी द्वारा पंजीकृत महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स का एक बड़ा हिस्सा आईटी उद्योग में है, जो सबसे बड़ा क्षेत्रीय समूह बनाता है। डिजिटलीकरण और इंटरनेट ने महिलाओं को पारंपरिक बाधाओं को पार कर वैश्विक बाजारों तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। सामाजिक उद्यमिता भी गति पकड़ रही है, जहां महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सतत विकास के क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। एमएसएमई मंत्रालय के उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर महिलाओं द्वारा संचालित एमएसएमई की हिस्सेदारी 20.5% है। इन इकाइयों ने कुल रोजगार सुजन में 18.73% और कुल निवेश में 11.15% का योगदान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 2023 की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि 69% ऋण खाते महिलाओं के हैं। भारत में 2023 तक 100 से अधिक यूनिकॉर्न बन चुके हैं, जिनमें से 10-15% महिला सह-संस्थापकों के नेतृत्व में हैं। नायका की फालगुनी नायर, मोर्चीकिंग की उपासना ताकू जैसी उद्यमी किशोरियों और युवतियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

महिला उद्यमिता की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। वित्तीय पहुंच, कौशल विकास और अनुकूल परिस्थितिकी तंत्र के निर्माण से महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन न केवल सामाजिक न्याय का विषय है, बल्कि यह भारत के समग्र और सतत विकास के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता भी है। महिलाओं की भागीदारी से भारत अधिक समान और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर हो सकता है।